

दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का अध्ययन: नेपाल-चीन सहयोग और भारत पर प्रभाव

कु. चन्दा यादव

शोध छात्रा

राजनीति विज्ञान विभाग

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश

दक्षिण एशिया की भू-राजनीति हाल के वर्षों में तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहाँ भारत-केंद्रित पारंपरिक क्षेत्रीय संरचना को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में नेपाल और चीन के बीच बढ़ता सहयोग विशेष महत्व रखता है। यह अध्ययन नेपाल-चीन संबंधों के उभरते राजनीतिक, आर्थिक, जुड़वों और रणनीतिक आयामों का विश्लेषण करता है तथा उनके भारत पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन करता है। शोध जो नव यथार्थवादी, लघु राज्य सिद्धांत और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नेपाल का चीन की ओर झुकाव पूर्ण समायोजन (Alignment) न होकर रणनीतिक हेजिंग और स्वायत्तता की खोज का परिणाम है। साथ ही, चीन की बढ़ती उपस्थिति हिमालयी क्षेत्र को एक सक्रिय रणनीतिक स्थान में परिवर्तित कर रही है, जिससे भारत की सामरिक गहराई और क्षेत्रीय भूमिका प्रभावित हो रही है। निष्कर्षतः, इस शोध पत्र के माध्यम से यह प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है

कि नेपाल-चीन सहयोग दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन के संरचनात्मक पुनर्संरचना का संकेत है, जो भारत को अपनी पड़ोसी नीति और क्षेत्रीय रणनीति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।

मुख्य शब्द: दक्षिण एशिया, भू राजनीति नेपाल-चीन, भारत, शक्ति संतुलन, लघु राज्य

परिचय

दक्षिण एशिया विश्व की सबसे जटिल और संवेदनशील भू-राजनीतिक संरचनाओं में से एक है, जहाँ ऐतिहासिक विरासत, सामरिक प्रतिस्पर्धा, भौगोलिक बाधाएँ और उभरती महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह क्षेत्र न केवल जनसंख्या, संसाधन और रणनीतिक अवस्थिति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत और चीन जैसी दो प्रमुख एशियाई शक्तियों के परस्पर संबंधों का भी प्रमुख मंच है। विशेषतः हिमालयी क्षेत्र, जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षा कवच माना जाता रहा है, आज सक्रिय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता जा रहा है। नेपाल, जो पारंपरिक रूप से भारत-केंद्रित विदेश नीति के लिए जाना जाता रहा है, हाल के वर्षों में अपनी कूटनीतिक दिशा में उल्लेखनीय परिवर्तन करता दिखाई देता है। चीन के साथ उसके राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में आई तीव्रता केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की व्यापक शक्ति-संरचना को भी प्रभावित कर रही है। चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI), कनेक्टिविटी परियोजनाएँ, अवसंरचनात्मक निवेश और कूटनीतिक सक्रियता ने नेपाल-चीन संबंधों को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है। यह उभार केवल आर्थिक नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से भू-रणनीतिक है। इस बदलते परिदृश्य में भारत की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक निकटता रही है, जिसे भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' (Neighbourhood First Policy) के अंतर्गत रणनीतिक रूप से भी सुदृढ़ किया गया था। किंतु नेपाल का चीन की ओर बढ़ता झुकाव भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में एक प्रकार की संरचनात्मक चुनौती उत्पन्न करता है। यह स्थिति भारत के लिए केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामरिक और सुरक्षा से जुड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है।

समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में छोटे राज्यों की भूमिका भी परिवर्तित हो रही है। नेपाल जैसे राज्य अब केवल बड़ी शक्तियों के प्रभाव में रहने वाले निष्क्रिय कर्ता (Actor) नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने हितों को संतुलित करने की रणनीति अपनाते हुए बहुपक्षीय विकल्प तलाश रहे हैं। इस संदर्भ में नेपाल का चीन के साथ सहयोग उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की अभिव्यक्ति भी हो सकता है और संरचनात्मक दबावों की प्रतिक्रिया भी। यह द्वंद्व इस अध्ययन को और अधिक विश्लेषणात्मक महत्व प्रदान करता है। यद्यपि भारत-नेपाल, नेपाल-चीन तथा भारत-चीन संबंधों पर अलग-अलग पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, परंतु त्रिकोणीय भू-राजनीतिक ढांचे में नेपाल-चीन सहयोग के भारत पर प्रभाव का समग्र, सैद्धांतिक और आलोचनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित है। अधिकांश अध्ययन द्विपक्षीय दृष्टिकोण तक सीमित रह गए हैं और दक्षिण एशिया की बदलती शक्ति-संरचना को समेकित रूप में समझने का प्रयास कम हुआ है। इसी शोध-रिक्तता (research gap) को भरने का प्रयास यह अध्ययन करता है। यह शोध दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति को नेपाल-चीन सहयोग के संदर्भ में समझते हुए भारत पर पड़ने वाले रणनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन न केवल क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन में हो रहे परिवर्तन को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार छोटे राज्य, बड़ी शक्तियों के बीच अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। इस दृष्टि से यह शोध दक्षिण एशियाई भू-राजनीतिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण अकादमिक योगदान प्रस्तुत करता है।

शोध के उद्देश्य

- नेपाल-चीन सहयोग के उभरते स्वरूप और उसके रणनीतिक आयामों का विश्लेषण करना।
- दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को समझना।
- नेपाल-चीन सहयोग के भारत की सामरिक, कूटनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।

शोध प्रश्न

- नेपाल-चीन सहयोग के प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक आयाम क्या हैं?
- नेपाल की विदेश नीति में चीन की ओर बढ़ते झुकाव के पीछे कौन-से संरचनात्मक और आंतरिक कारक कार्य कर रहे हैं?
- नेपाल-चीन सहयोग भारत की सामरिक, कूटनीतिक और सुरक्षा स्थिति को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है?

सैद्धांतिक ढांचा

यह अध्ययन दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति को समझने के लिए मुख्यतः नव यथार्थवाद (Neo-Realism), लघु राज्य सिद्धांत (Small State Theory) के सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है।

1. नव यथार्थवाद

नव यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है और राज्य अपनी सुरक्षा तथा शक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इस दृष्टिकोण से नेपाल-चीन सहयोग को भारत-चीन शक्ति-संघर्ष की संरचनात्मक पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। चीन की बढ़ती उपस्थिति और भारत की सुरक्षा चिंता को शक्ति-संतुलन (Balance of Power) तथा सुरक्षा दुविधा (Security Dilemma) की अवधारणाओं के माध्यम से समझा गया है।

2. लघु राज्य सिद्धांत

यह सिद्धांत मानता है कि छोटे राज्य बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। नेपाल का चीन के साथ सहयोग इस संदर्भ में बैलेंसिंग और हेजिंग रणनीति के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ वह भारत पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और अपने विकल्पों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

शोध प्रविधि

यह अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। शोध नेपाल-चीन सहयोग और उसके भारत पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक प्रभावों के समालोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें अकादमिक जर्नल, सरकारी दस्तावेज, नीति रिपोर्ट, थिंक टैंक प्रकाशन और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय स्रोत शामिल हैं। विश्लेषण के लिए कंटेंट एनालिसिस और तुलनात्मक विधि अपनाई गई है।

सैद्धांतिक आधार के रूप में नव यथार्थवाद, लघु राज्य सिद्धांत के दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है, ताकि संरचनात्मक दबावों, शक्ति-संतुलन और रणनीतिक व्यवहार को स्पष्ट किया जा सके।

साहित्य समीक्षा

दक्षिण एशिया की भू-राजनीति पर उपलब्ध साहित्य मुख्यतः भारत की क्षेत्रीय भूमिका और भारत-चीन प्रतिस्पर्धा के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है। Sumit Ganguly (2012) और C. Raja Mohan (2003) जैसे विद्वानों ने भारत की पड़ोसी नीति और क्षेत्रीय प्रभुत्व की अवधारणा का विश्लेषण किया है, जिसमें नेपाल को भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना गया है। ये अध्ययन भारत-नेपाल संबंधों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक निकटता के ढांचे में देखते हैं।

नेपाल-चीन संबंधों पर बढ़ते साहित्य में Shiv Kumar (2018), Swaran Singh (2019) और ADB Reports ने चीन की कनेक्टिविटी रणनीति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और नेपाल में बढ़ते अवसंरचनात्मक निवेश को रेखांकित किया है। इन अध्ययनों में नेपाल को चीन की दक्षिण एशियाई रणनीति का उभरता प्रवेश-द्वार (gateway) माना गया है।

भारत-चीन प्रतिस्पर्धा पर John Garver (2016), Fravel (2008) और Brahma Chellaney (2017) जैसे विद्वानों ने हिमालयी क्षेत्र को रणनीतिक संघर्ष क्षेत्र के रूप में विश्लेषित किया है। इन अध्ययनों में छोटे राज्यों की भूमिका का उल्लेख तो है, लेकिन नेपाल को प्रायः परिधीय संदर्भ में ही देखा गया है।

छोटे राज्य सिद्धांत पर Neumann & Gstöhl (2006) और Hey (2003) ने यह स्पष्ट किया है कि छोटे राज्य बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन और हेजिंग रणनीति अपनाते हैं। इस सैद्धांतिक ढांचे में नेपाल की चीन नीति को समझने की संभावना बनती है, परंतु अधिकांश अध्ययनों में इसे भारत-चीन प्रतिस्पर्धा से सीधे जोड़कर नहीं देखा गया है।

महत्वपूर्ण यह है कि उपलब्ध साहित्य प्रायः द्विपक्षीय विश्लेषण (India–Nepal या Nepal–China) तक सीमित है। नेपाल-चीन सहयोग के भारत पर भू-राजनीतिक प्रभाव का समेकित, त्रिकोणीय और सैद्धांतिक अध्ययन अत्यंत सीमित है। यही विश्लेषणात्मक रिक्तता (analytical gap) इस शोध का केंद्रीय आधार है।

यह अध्ययन विद्यमान साहित्य से आगे बढ़ते हुए नेपाल-चीन सहयोग को भारत की रणनीतिक स्थिति और दक्षिण एशिया की बदलती शक्ति-संरचना के व्यापक संदर्भ में रखकर एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

नेपाल-चीन सहयोग के उभरते आयाम

पिछले एक दशक में नेपाल और चीन के बीच सहयोग में उल्लेखनीय गहराई और विस्तार देखने को मिला है। यह संबंध अब केवल औपचारिक कूटनीति या सीमित व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, अवसंरचनात्मक और सुरक्षा आयामों को समाहित करता हुआ एक व्यापक रणनीतिक स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। यह परिवर्तन दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है, जहाँ हिमालयी क्षेत्र निष्क्रिय सीमांत न रहकर सक्रिय रणनीतिक स्पेस बनता जा रहा है।

1. राजनीतिक और कूटनीतिक आयाम

नेपाल-चीन संबंधों में राजनीतिक स्तर पर निरंतर उच्चस्तरीय संवाद और परस्पर समर्थन की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। नेपाल ने 'वन-चाइना पॉलिसी' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बार-बार दोहराया है और तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर चीन के आंतरिक हितों का समर्थन किया है। इसके बदले में चीन ने नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्थिरता के समर्थन को प्राथमिकता दी है। यह आपसी समर्थन केवल औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक विश्वास-निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है।¹

नेपाल के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य में भी चीन की सक्रिय कूटनीतिक भूमिका देखी जा सकती है, जहाँ उसने विभिन्न राजनीतिक दलों और नेतृत्व के साथ संवाद बढ़ाया है। यह पहल नेपाल की घरेलू राजनीति को स्थिर रखने और अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित करने की रणनीति के रूप में देखी जा सकती है।²

2. आर्थिक सहयोग और निवेश

आर्थिक क्षेत्र में नेपाल-चीन सहयोग का विस्तार सबसे अधिक दृष्टिगोचर है। चीन नेपाल के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में शामिल हो चुका है और द्विपक्षीय व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। चीनी निवेश विशेष रूप से ऊर्जा, पर्यटन, दूरसंचार और निर्माण क्षेत्र में केंद्रित रहा है।³

नेपाल का 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) में सम्मिलित होना इस आर्थिक साझेदारी को एक भू-रणनीतिक आयाम प्रदान करता है। BRI के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाएँ केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे नेपाल को भारत-निर्भर व्यापार मार्गों से आंशिक रूप से मुक्त करने की क्षमता रखती हैं। यह पहल नेपाल के लिए विकल्पों के विस्तार का साधन है, तो चीन के लिए दक्षिण एशिया में गहरी पैठ का माध्यम।⁴

3. कनेक्टिविटी और अवसंरचना

नेपाल-चीन सहयोग का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक आयाम कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हिमालयी क्षेत्र में सड़क, रेल और सीमा-पार संपर्क परियोजनाएँ नेपाल को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। प्रस्तावित काठमांडू-केरुंग रेलवे परियोजना केवल परिवहन परियोजना नहीं है, बल्कि यह नेपाल की भू-आर्थिक दिशा को पुनर्परिभाषित करने वाली पहल है।⁵

इन परियोजनाओं के माध्यम से चीन न केवल नेपाल में अपनी भौतिक उपस्थिति बढ़ा रहा है, बल्कि वह हिमालयी बाधाओं को पार कर दक्षिण एशिया तक पहुँच बनाने की दीर्घकालिक रणनीति को भी सुदृढ़ कर रहा है। यह भारत की पारंपरिक सामरिक गहराई के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न करता है।

4. सुरक्षा और सीमा-संबंधी सहयोग

हाल के वर्षों में नेपाल-चीन संबंधों में सुरक्षा आयाम भी उभरकर सामने आया है। दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन, कानून-प्रवर्तन सहयोग और सूचना-साझाकरण को लेकर संवाद बढ़ा है। नेपाल द्वारा तिब्बती शरणार्थी गतिविधियों पर नियंत्रण और सीमा सुरक्षा को लेकर चीनी चिंताओं को प्राथमिकता देना इस सहयोग का स्पष्ट संकेत है।⁶

यद्यपि नेपाल आधिकारिक रूप से किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है, फिर भी सुरक्षा सहयोग का यह विस्तार भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। हिमालयी क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत की सुरक्षा गणनाओं को प्रभावित करती है और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को पुनर्संरचित करती है।

5. रणनीतिक निहितार्थ

नेपाल-चीन सहयोग का यह बहुआयामी विस्तार केवल द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की व्यापक भू-राजनीतिक संरचना में परिवर्तन का संकेत है। नेपाल अब केवल भारत की परिधि में स्थित राज्य नहीं रह गया है, बल्कि वह सक्रिय रूप से अपने रणनीतिक विकल्पों का विस्तार कर रहा है। यह स्थिति छोटे राज्य की उस

प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहाँ वह बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपनी स्वायत्तता को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।⁷

इस संदर्भ में नेपाल-चीन सहयोग को न तो केवल विकासात्मक साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है और न ही केवल कूटनीतिक औपचारिकता के रूप में। यह एक संरचनात्मक भू-राजनीतिक पुनर्संरचना है, जिसके दूरगामी प्रभाव भारत की क्षेत्रीय भूमिका और दक्षिण एशिया के शक्ति-संतुलन पर पड़ रहे हैं।

नेपाल-चीन सहयोग का भारत पर भू-राजनीतिक प्रभाव

नेपाल और चीन के बीच बढ़ता सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक भू-राजनीतिक निहितार्थ भारत की रणनीतिक स्थिति, क्षेत्रीय भूमिका और सुरक्षा गणनाओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के पारंपरिक प्रभाव-क्षेत्र की संरचना को चुनौती देती है और दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन को पुनर्परिभाषित करती है।

1. सामरिक और सुरक्षा प्रभाव

भारत की सुरक्षा नीति ऐतिहासिक रूप से हिमालयी क्षेत्र को प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में देखती रही है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तरी सीमांत की सामरिक गहराई (strategic depth) का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती रही है। किंतु नेपाल-चीन सहयोग के विस्तार, विशेषकर कनेक्टिविटी और अवसंरचना परियोजनाओं के संदर्भ में, इस सामरिक गणना में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है।¹

हिमालयी क्षेत्र में चीनी अवसंरचना परियोजनाएँ और सीमा-पार संपर्क भारत के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती उत्पन्न करते हैं। ये पहल चीन को भारत की परिधि तक भौतिक पहुँच की संभावनाएँ प्रदान करती हैं, जिससे भारत की सुरक्षा दुविधा (security dilemma) और अधिक गहरी होती है।² यद्यपि नेपाल किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है, फिर भी सुरक्षा सहयोग का यह विस्तार भारत की सामरिक चिंताओं को बढ़ाता है।

2. कूटनीतिक प्रभाव और प्रभाव-क्षेत्र की चुनौती

भारत लंबे समय से नेपाल को अपने प्राकृतिक प्रभाव-क्षेत्र (sphere of influence) के अंतर्गत देखता आया है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों ने भारत को नेपाल में एक विशेष कूटनीतिक स्थिति प्रदान की थी। किंतु चीन की सक्रिय कूटनीति और नेपाल के साथ गहरे होते संबंध भारत की इस पारंपरिक स्थिति को चुनौती देते हैं।³

नेपाल द्वारा चीन के साथ बढ़ते राजनीतिक समन्वय और बहुपक्षीय मंचों पर चीन के पक्ष में झुकाव भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं के लिए एक संरचनात्मक चुनौती बनता जा रहा है। यह स्थिति भारत की 'Neighbourhood First Policy' की प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।⁴

3. क्षेत्रीय नेतृत्व और शक्ति-संतुलन पर प्रभाव

दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका केवल एक बड़े राज्य की नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय नेता (regional leader) की भी रही है। किंतु नेपाल-चीन सहयोग के गहराते स्वरूप से क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन में परिवर्तन स्पष्ट होता है। चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत की क्षेत्रीय प्रधानता (regional primacy) को आंशिक रूप से क्षीण करती है।⁵

यह परिवर्तन केवल नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य छोटे राज्यों के लिए भी एक संकेत है कि भारत के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हैं। इस प्रकार, नेपाल-चीन सहयोग एक मिसाल के रूप में उभरता है, जो भारत की पारंपरिक नेतृत्व भूमिका को चुनौती देता है।

4. आर्थिक और कनेक्टिविटी आयाम

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और ऐतिहासिक व्यापार मार्गों ने भारत को नेपाल की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका दी है। किंतु चीन के साथ नेपाल की बढ़ती आर्थिक साझेदारी और वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजनाएँ इस संरचना को बदल रही हैं।⁶

काठमांडू-केरुंग रेलवे जैसी परियोजनाएँ नेपाल को भारत-निर्भर मार्गों से आंशिक रूप से मुक्त करने की क्षमता रखती हैं। यह भारत के लिए आर्थिक प्रभाव के क्षरण का संकेत है और क्षेत्रीय भू-अर्थशास्त्र (geo-economics) में परिवर्तन का द्योतक भी।⁷

5. सामरिक दुविधा और नीति-चुनौती

नेपाल-चीन सहयोग का भारत पर प्रभाव केवल बाहरी चुनौती नहीं है, बल्कि यह भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया के लिए भी एक परीक्षा है। भारत को एक ओर नेपाल की संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करना है, वहीं दूसरी ओर अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों की रक्षा भी करनी है। यह द्वंद्व भारत की कूटनीतिक रणनीति को अधिक जटिल बनाता है।⁸ इस संदर्भ में नेपाल-चीन सहयोग भारत के लिए एक चेतावनी संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि पारंपरिक प्रभाव-आधारित नीति अब पर्याप्त नहीं है। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अधिक संवेदनशील, समावेशी और साझेदारी-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

6. समग्र मूल्यांकन

समग्र रूप से देखा जाए तो नेपाल-चीन सहयोग भारत के लिए केवल एक द्विपक्षीय चुनौती नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की व्यापक भू-राजनीतिक पुनर्संरचना का हिस्सा है। यह भारत की सामरिक गहराई, कूटनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय नेतृत्व तीनों को प्रभावित करता है। इस प्रभाव को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि बदलते अंतरराष्ट्रीय ढांचे की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए।⁹ इस प्रकार, नेपाल-चीन सहयोग भारत को अपनी क्षेत्रीय नीति, पड़ोसी दृष्टिकोण और सामरिक प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करता है।

दक्षिण एशिया में बदलता शक्ति-संतुलन

दक्षिण एशिया की भू-राजनीति लंबे समय तक भारत-केंद्रित शक्ति-संरचना पर आधारित रही है, जहाँ भारत को क्षेत्रीय व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ माना जाता था। ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामरिक कारणों से भारत का प्रभाव

अपने पड़ोसी देशों पर अपेक्षाकृत व्यापक रहा है। किंतु इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के बाद यह संरचना धीरे-धीरे पुनर्संरचित होती दिखाई देती है। चीन की बढ़ती सक्रियता और छोटे राज्यों की बदलती रणनीति ने दक्षिण एशिया के शक्ति-संतुलन को गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है।

1. क्षेत्रीय शक्ति-संरचना का परिवर्तन

शक्ति-संतुलन सिद्धांत के अनुसार, जब किसी क्षेत्र में एक शक्ति का प्रभुत्व बढ़ता है, तो अन्य शक्तियाँ संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति इसी प्रक्रिया का उदाहरण है। चीन अब केवल सीमांत पड़ोसी नहीं, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक अभिनेता के रूप में क्षेत्र में सक्रिय है।¹ यह स्थिति भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय प्रधानता को चुनौती देती है और एक बहुध्रुवीय (multipolar) प्रवृत्ति को जन्म देती है।

नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे छोटे राज्य इस बदलती संरचना में चीन को एक वैकल्पिक साझेदार के रूप में देखने लगे हैं। यह रुझान दक्षिण एशिया की शक्ति-संरचना को अधिक जटिल और प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है।²

2. भारत-चीन प्रतिस्पर्धा और उसका क्षेत्रीय प्रभाव

दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का केंद्रीय तत्व भारत-चीन प्रतिस्पर्धा है। दोनों एशियाई शक्तियाँ न केवल सीमा पर, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव के स्तर पर भी एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभर रही हैं। चीन की आर्थिक कूटनीति, अवसंरचनात्मक निवेश और कनेक्टिविटी परियोजनाएँ भारत के पारंपरिक प्रभाव-क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं।³ यह प्रतिस्पर्धा केवल द्विपक्षीय नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ता है। छोटे राज्य इस प्रतिस्पर्धा का उपयोग अपने हितों को अधिकतम करने के लिए कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय संतुलन और अधिक तरल (fluid) होता जा रहा है।⁴

3. छोटे राज्यों की भूमिका और रणनीतिक स्वायत्तता

दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन के बदलते स्वरूप में छोटे राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप से ये राज्य भारत पर अधिक निर्भर रहे हैं, किंतु अब वे चीन सहित अन्य बाहरी शक्तियों के साथ भी संबंध विकसित कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति रणनीतिक स्वायत्तता की खोज को दर्शाती है।⁵ नेपाल का चीन के साथ सहयोग इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। यह केवल आर्थिक लाभ का प्रश्न नहीं है, बल्कि अपने विकल्पों का विस्तार करने और किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की रणनीति है। इस प्रकार, छोटे राज्य अब निष्क्रिय उपग्रह नहीं, बल्कि सक्रिय संतुलनकर्ता (active balancers) के रूप में उभर रहे हैं।⁶

4. भू-अर्थशास्त्र और शक्ति-संतुलन

दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन का स्वरूप अब केवल सैन्य या कूटनीतिक नहीं रह गया है, बल्कि उसमें भू-अर्थशास्त्र (geo-economics) की भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है। चीन की निवेश-आधारित कूटनीति, ऋण परियोजनाएँ और अवसंरचना निर्माण क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं।⁷ नेपाल-चीन सहयोग इस भू-अर्थशास्त्रीय बदलाव का स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ आर्थिक साझेदारी के माध्यम से रणनीतिक प्रभाव का विस्तार किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन को अधिक जटिल और बहुस्तरीय बनाती है।

5. भारत की बदलती क्षेत्रीय स्थिति

इस बदलते परिदृश्य में भारत की क्षेत्रीय स्थिति भी पुनर्परिभाषित हो रही है। भारत अब एकमात्र प्रभावशाली शक्ति नहीं रह गया है, बल्कि उसे चीन जैसी बाहरी शक्ति के साथ क्षेत्रीय प्रभाव साझा करना पड़ रहा है। यह स्थिति भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उसे एक ओर अपने नेतृत्व को बनाए रखना है और दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों की बदलती प्राथमिकताओं को भी स्वीकार करना है।⁸ यह परिवर्तन भारत को अधिक सहकारी, समावेशी और साझेदारी-आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि प्रभाव-आधारित या वर्चस्व-आधारित नीति अब उतनी प्रभावी नहीं रह गई है।

6. संरचनात्मक पुनर्संरचना और दीर्घकालिक निहितार्थ

दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन का यह परिवर्तन अस्थायी नहीं, बल्कि संरचनात्मक प्रतीत होता है। चीन की दीर्घकालिक रणनीति, छोटे राज्यों की बदलती भूमिका और भारत की पुनर्संरचित क्षेत्रीय नीति मिलकर एक नई भू-राजनीतिक संरचना को जन्म दे रहे हैं।⁹

इस संदर्भ में नेपाल-चीन सहयोग केवल एक द्विपक्षीय घटना नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में व्यापक भू-राजनीतिक संक्रमण (geopolitical transition) का हिस्सा है। यह संक्रमण क्षेत्रीय राजनीति को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, बहुध्रुवीय और गतिशील बनाता जा रहा है।

(सैद्धांतिक-अनुभवजन्य समेकन और आलोचनात्मक विश्लेषण)

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नेपाल-चीन सहयोग को केवल द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के रूप में देखना अपर्याप्त होगा। यह सहयोग दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक संरचना में हो रहे व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है, जिसमें शक्ति-संतुलन, क्षेत्रीय नेतृत्व और छोटे राज्यों की भूमिका पुनर्परिभाषित हो रही है। नेपाल का चीन की ओर बढ़ता झुकाव किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि संरचनात्मक दबावों, रणनीतिक विकल्पों और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का सम्मिलित प्रभाव है।

1. सैद्धांतिक ढांचे और वास्तविकता का समन्वय

नियो-रीयलिस्ट परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेपाल-चीन सहयोग भारत-चीन शक्ति-संघर्ष की संरचनात्मक परिणति प्रतीत होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की अराजक प्रकृति राज्यों को अपनी सुरक्षा और विकल्पों का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है।¹ इस संदर्भ में नेपाल का चीन के साथ सहयोग हेजिंग रणनीति का उदाहरण है, जहाँ वह भारत पर अत्यधिक निर्भरता को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यह व्यवहार छोटे राज्य सिद्धांत के अनुरूप है, जो मानता है कि छोटे राज्य बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपनी स्वायत्तता सुरक्षित करते हैं।²

यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि नेपाल का यह व्यवहार पूर्णतः बैंडवैगनिंग नहीं है, बल्कि सीमित और चयनात्मक सहयोग पर आधारित है। इससे यह संकेत मिलता है कि नेपाल चीन के साथ संबंधों को एक विकल्प के रूप में देख रहा है, न कि पूर्ण रणनीतिक संरेखण के रूप में। यह अंतर इस अध्ययन को अधिक सूक्ष्म बनाता है।

2. भू-राजनीतिक संरचना का पुनर्संरचन

नेपाल-चीन सहयोग हिमालयी क्षेत्र को एक सक्रिय भू-राजनीतिक स्पेस में परिवर्तित कर रहा है। पारंपरिक रूप से यह क्षेत्र भारत की सामरिक गहराई के रूप में देखा जाता रहा है, किंतु अब यह प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव-क्षेत्र में बदलता जा रहा है।³ यह परिवर्तन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक है, क्योंकि कनेक्टिविटी, अवसंरचना और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से चीन इस क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति बना रहा है। यह स्थिति मैकिंडर और स्पाइकमैन के भू-राजनीतिक सिद्धांतों की समकालीन प्रासंगिकता को भी रेखांकित करती है, जहाँ सीमांत क्षेत्रों पर नियंत्रण को क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए निर्णायक माना गया है।⁴

3. भारत की रणनीतिक दुविधा

इस अध्ययन का एक केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि नेपाल-चीन सहयोग भारत के लिए एक रणनीतिक दुविधा उत्पन्न करता है। भारत एक ओर नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों की रक्षा भी करना चाहता है। यह द्वंद्व भारत की पड़ोसी नीति को जटिल बनाता है।⁵

भारत की पारंपरिक प्रभाव-आधारित नीति अब पर्याप्त नहीं प्रतीत होती, क्योंकि छोटे राज्य विकल्पों के विस्तार की नीति अपना रहे हैं। यह स्थिति भारत को अधिक साझेदारी-आधारित और संवेदनशील कूटनीति अपनाने के लिए बाध्य करती है।

4. छोटे राज्य की एजेंसी और सक्रिय भूमिका

यह अध्ययन छोटे राज्यों को केवल बड़ी शक्तियों के प्रभाव में रहने वाले निष्क्रिय अभिनेता के रूप में देखने की धारणा को चुनौती देता है। नेपाल का व्यवहार यह दर्शाता है कि छोटे राज्य भी सक्रिय रूप से अपनी भू-राजनीतिक स्थिति का उपयोग कर सकते हैं।⁶ नेपाल-चीन सहयोग को इस दृष्टि से रणनीतिक विवेक की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है, जहाँ नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति को leverage बनाकर लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। यह प्रवृत्ति दक्षिण एशिया के अन्य छोटे राज्यों में भी देखी जा सकती है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति अधिक बहुध्रुवीय और प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है।

5. भू-अर्थशास्त्र और रणनीतिक प्रभाव

चीन की आर्थिक कूटनीति और अवसंरचना परियोजनाएँ केवल विकासात्मक साधन नहीं हैं, बल्कि वे रणनीतिक प्रभाव के उपकरण भी हैं। नेपाल-चीन सहयोग में भू-अर्थशास्त्र की भूमिका इस बात को स्पष्ट करती है कि आधुनिक शक्ति-संतुलन केवल सैन्य या कूटनीतिक आयामों तक सीमित नहीं है।⁷ इस संदर्भ में नेपाल का BRI में सम्मिलित होना भारत के लिए केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि भू-रणनीतिक संकेत भी है। यह भारत को अपनी कनेक्टिविटी और विकास-केंद्रित कूटनीति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता का संकेत देता है।

6. समग्र विमर्श

समग्र रूप से, यह अध्ययन यह स्थापित करता है कि नेपाल-चीन सहयोग न तो आकस्मिक है और न ही अस्थायी। यह दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का संरचनात्मक अंग है। भारत-चीन प्रतिस्पर्धा, छोटे राज्यों की बदलती भूमिका और भू-अर्थशास्त्र का उभार मिलकर एक नई क्षेत्रीय संरचना को जन्म दे रहे हैं।⁸ इस प्रकार, नेपाल-चीन सहयोग को भारत के विरुद्ध शून्य-योग (zero-sum) खेल के रूप में देखना सीमित दृष्टिकोण होगा। इसे एक व्यापक संक्रमण के हिस्से के रूप में समझना अधिक सैद्धांतिक रूप से संगत और विश्लेषणात्मक रूप से उपयोगी है।

निष्कर्ष(Conclusion)

नेपाल-चीन सहयोग बहुआयामी और संरचनात्मक प्रकृति का है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नेपाल-चीन संबंध केवल आर्थिक या कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक, अवसंरचनात्मक, कनेक्टिविटी और सुरक्षा आयामों को समाहित करते हुए एक व्यापक रणनीतिक स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं। नेपाल की विदेश नीति में स्पष्ट पुनर्संरक्षण देखा जा सकता है। नेपाल पारंपरिक भारत-केंद्रित नीति से आगे बढ़कर बहुविकल्पीय (multi-vector) रणनीति अपना रहा है, जहाँ चीन एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरता है। चीन की उपस्थिति हिमालयी क्षेत्र की भू-राजनीति को पुनर्परिभाषित कर रही है। कनेक्टिविटी परियोजनाएँ और अवसंरचना निवेश हिमालय को निष्क्रिय सीमांत से सक्रिय रणनीतिक स्पेस में परिवर्तित कर रहे हैं। भारत की सामरिक गहराई और पारंपरिक प्रभाव-क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। नेपाल-चीन सहयोग भारत की क्षेत्रीय प्रधानता और सामरिक गणनाओं को चुनौती देता है, जिससे भारत की सुरक्षा दुविधा गहरी होती है। दक्षिण एशिया का शक्ति-संतुलन अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और बहुध्रुवीय बन रहा है। भारत अब क्षेत्र में एकमात्र प्रभावशाली शक्ति नहीं रहा, बल्कि चीन की सक्रिय भूमिका क्षेत्रीय संरचना को पुनर्संरचित कर रही है। छोटे राज्य निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय संतुलनकर्ता के रूप में उभर रहे हैं। नेपाल का व्यवहार Small State Theory के अनुरूप है, जहाँ वह बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करता है। नेपाल-चीन सहयोग शून्य-योग नहीं, बल्कि रणनीतिक हेजिंग का उदाहरण है। यह पूर्ण बैंडवैगनिंग नहीं, बल्कि चयनात्मक और हित-आधारित संलग्नता है, जिससे नेपाल अपने विकल्पों का विस्तार कर रहा है। भारत की पड़ोसी नीति के लिए यह एक चेतावनी संकेत है। अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रभाव-आधारित नीति अब पर्याप्त नहीं है और भारत को अधिक साझेदारी-आधारित, संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भू-अर्थशास्त्र अब भू-राजनीति का निर्णायक घटक बन चुका है। चीन की आर्थिक कूटनीति और निवेश-रणनीति क्षेत्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित कर रही है, जिससे शक्ति-संतुलन का स्वरूप बदल रहा है। नेपाल-चीन सहयोग दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक संक्रमण का प्रतीक है। यह सहयोग एक व्यापक संरचनात्मक बदलाव का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय राजनीति को दीर्घकालिक रूप से पुनर्संरचित कर रहा है।

नीतिगत निहितार्थ एवं सुझाव

- भारत को प्रभाव-आधारित नीति से साझेदारी-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना चाहिए। नेपाल के साथ संबंधों में संवेदनशीलता, सम्मान और परस्पर लाभ पर आधारित कूटनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कनेक्टिविटी और विकास-केंद्रित कूटनीति को सुदृढ़ किया जाए। भारत को नेपाल में अवसंरचना, ऊर्जा और सीमा-पार संपर्क परियोजनाओं में अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ विश्वास-निर्माण (Confidence Building) पर बल दिया जाए। संवाद, लोगों-से-लोगों के संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति को सक्रिय किया जाना चाहिए। नेपाल की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान किया जाए। दबाव-आधारित दृष्टिकोण के बजाय विकल्पों के विस्तार को स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाए। क्षेत्रीय बहुपक्षीय मंचों को पुनर्जीवित किया जाए। BIMSTEC, BBIN जैसे मंचों को सक्रिय कर क्षेत्रीय सहयोग को गहरा किया जाए। भू-अर्थशास्त्र को नीति का केंद्रीय घटक बनाया जाए। व्यापार, निवेश और विकास सहयोग को भारत की पड़ोसी नीति का मुख्य स्तंभ बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा संवाद को संस्थागत रूप दिया जाए। सीमा-प्रबंधन, आपदा सहयोग और आंतरिक सुरक्षा विषयों पर नियमित तंत्र विकसित किए जाएँ।

संदर्भ सूची (References)

- अचार्य, ए. (2014). द एंड ऑफ अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर [अमेरिकी वैश्विक व्यवस्था का अंत]. पोलिटी प्रेस.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक. (2020). नेपाल एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन [नेपाल और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण]. एडीबी पब्लिकेशंस.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक. (2021). साउथ एशिया इकोनॉमिक आउटलुक [दक्षिण एशिया आर्थिक आउटलुक]. एडीबी पब्लिकेशंस.

- ब्रॉटिंगम, डी. (2009). द ड्रैगन्स गिफ्ट: द रियल STORY ऑफ चाइना इन अफ्रीका [द ड्रैगन गिफ्ट: अफ्रीका में चीन की वास्तविक कहानी]. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- बुज़ान, बी., एवं वेवर, ओ. (2003). रीजन्स एंड पावर्स: द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी [क्षेत्र और शक्तियां: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की संरचना]. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
- चेल्लानी, बी. (2017). चाइनाज़ एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया [दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता रणनीतिक प्रभाव]. सर्वाइवल, 59(2), 91-104.
<https://doi.org/10.1080/00396338.2017.1301465>
- फ्रेवल, एम. टी. (2008). स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स, सिक्योर नेशन: कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन चाइनाज़ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स [मजबूत सीमाएँ, सुरक्षित राष्ट्र: चीन के क्षेत्रीय विवादों में सहयोग और संघर्ष]. प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस.
- गांगुली, एस. (2012). इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी: रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट [भारत की विदेश नीति: अतीत और भविष्य]. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- गार्वर, जे. डब्ल्यू. (2016). प्रोट्रैक्टेड कॉन्टेस्ट: सिनो-इंडियन राइवलरी इन द ट्वेंटीथ सेंचुरी [लंबा विवाद: बीसवीं सदी में भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता]. यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन प्रेस.
- हे, जे. ए. के. (2003). स्मॉल स्टेट्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स: एक्सप्लेनिंग फॉरेन POLICY बिहेवियर [विश्व राजनीति में छोटे राज्य: विदेश नीति के व्यवहार की व्याख्या]. लिन रीनर पब्लिशर्स.
- इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप. (2019). चाइनाज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द हिमालयाज [हिमालय में चीन की सुरक्षा चिंताएं] (एशिया रिपोर्ट).
- कुमार, एस. (2018). नेपाल एंड चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव [नेपाल और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल]. जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, 77(3), 645-662.
<https://doi.org/10.1017/S002191181800060X>

- मैकिंडर, एच. जे. (1904). द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री [इतिहास का भौगोलिक धुरी]. द ज्योग्राफिकल जर्नल, 23(4), 421-437. <https://doi.org/10.2307/1775498>
- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार. (बिना तिथि). नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स [पड़ोसी पहले नीति के दस्तावेज़]. एमईए पब्लिकेशंस.
- परराष्ट्र मंत्रालय, नेपाल सरकार. (बिना तिथि). नेपाल-चाइना रिलेशंस ओवरव्यू [नेपाल-चीन संबंधों का अवलोकन]. नेपाल सरकार.
- मोहन, सी. आर. (2003). क्रॉसिंग द रुबिकॉन: द शेपिंग ऑफ इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी [क्रॉसिंग द रुबिकॉन: भारत की नई विदेश नीति का आकार]. पेंगुइन बुक्स.
- मोहन, सी. आर. (2015). मोदीज वर्ल्ड: एक्सपेंडिंग इंडियाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस [मोदी की दुनिया: भारत के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार]. हार्परकोलिनस.
- न्यूमैन, आई. बी., एवं गस्टोहल, एस. (2006). स्मॉल स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस [अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में छोटे राज्य]. यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन प्रेस.
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. (2020). चाइना-नेपाल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस [चीन-नेपाल कनेक्टिविटी परियोजनाएं और रणनीतिक निहितार्थ] (ओआरएफ इश्यू ब्रीफ).
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. (2021). चाइनाज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी इन नेपाल [नेपाल में चीन की बुनियादी ढांचा कूटनीति] (ओआरएफ इश्यू ब्रीफ).
- पंत, एच. वी. (2019). इंडियाज फॉरेन पॉलिसी: एन ओवरव्यू [भारत की विदेश नीति: एक अवलोकन]. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- पंत, एच. वी., एवं जोशी, वाई. (2017). द यूएस पिवट एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी [अमेरिकी पिवट और भारतीय विदेश नीति]. पालग्रेव मैकमिलन.

- स्कॉट, डी. (2018). चाइना एंड साउथ एशिया: स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस [चीन और दक्षिण एशिया: रणनीतिक निहितार्थ]. इंटरनेशनल अफेयर्स, 94(2), 375-392.
<https://doi.org/10.1093/ia/iix238>
- सिंह, एस. (2019). चाइनाज़ ग्रोइंग एंगेजमेंट इन नेपाल [नेपाल में चीन की बढ़ती भागीदारी]. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, 43(2), 99-113.
<https://doi.org/10.1080/09700161.2019.1584726>
- स्पाइकमैन, एन. जे. (1944). द Geography ऑफ द पीस [शांति का भूगोल]. हारकोर्ट, ब्रेस एंड कंपनी.
- वॉल्ट्ज, के. एन. (1979). थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स [अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत]. मैकग्रॉ-हिल.